station caters to the needs of the public of Perambalur district. Express trains, Vaigai Express, Pandian Express, Pallavan Express, Rock Fort Express stop at this station. Thousands of rail users use this station daily for boarding and alighting. It is an important station. But, provision of a food/tea stall is missing. The passengers need the facility for taking snacks and tea/coffee. Provision of a food/tea stall in the Ariyalur railway station will take care of better passenger amenities.

The pathway is much lower than the platform. This results in injuries to passengers, who get down from the platform. If the pathway is laid, it will avoid injuries to the users. This will take care of the safety of thousands of passengers, who use the railway facilities every day.

Sir, I hope the Railway Minister will accede to the requests which I have raised. Thank you.

TAX EXEMPTION ON HYDEL POWER GENERATION

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश): सभापति महोदय, सभी प्रदेश सरकारें आज गम्भीर आर्थिक संकट से गुजर रही हैं तथा अपने संसाधन बढ़ाने के लिए विभिन्न स्त्रोतों की खोज कर रही हैं। केन्द्र सरकार उन सभी प्रदेशों को उनके क्षेत्र में निकलने वाले तेल, कोयला या अन्य खनिजों पर रायल्टी देती है। हिमाचल प्रदेश में अपार जल संपदा से विद्युत उत्पादन हो सकता है जिससे पूरे उत्तर भारत की बिजली की आवश्यकता पूरी हो सकती है। भारत सरकार ने प्रदेश में लगने वाली नई बिजली की परियोजनाओं में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली रायल्टी के रूप में प्रदेश सरकार को देने का निर्णय लिया है परन्तु भाखड़ा, नांगल व व्यास सतलुज परियोजनाओं में इस सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है। हिमाचल की भूमि पर बहने वाले पानी से पैदा होने वाली बिजली से प्रदेश को कुछ नहीं मिल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव के माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि इस विद्युत उत्पादन पर जनरेशन टैक्स लगाने की इजाजत दे किन्तु आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ जिससे प्रदेश सरकार गंभीर आर्थिक संकट में जकड़ गई है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण हिमाचल प्रदेश की गंभीर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर शीघ्रतिशीघ्र उपरोक्त परियोजनाओं में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली प्रदेश को दिलवाए तथा जल विद्युत पर जनरेशन टैक्स लगाने की इजाजत दे।

REQUEST TO REPEAL I.M.D.T. ACT

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): I would like to draw the attention of the Union Home Ministry towards an urgent necessity of repealing the illegal Migrants determiniation by Tribunal Act (IMDT Act), 1983. Continuance of such an anti-national and discriminatory law is detrimental to the national security and sovereignty of India. It has encouraged large-scale